भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
08.02.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 947 का उत्तर

ओडिशा में चल रही/लंबित रेल परियोजनाएं

947. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में विशेष रूप से ओडिशा में चल रही और लंबित रेल परियोजनाओं का परियोजना क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में नई लाइनों के विकास/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;
(ग) रेलवे द्वारा ओडिशा में उक्त लंबित रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) उपरोक्त में से कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और
(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

s.k

ओडिशा में चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं के संबंध में 08.02.2023 को लोक सभा में श्री रमेश चन्द्र माझी के अतारांकित प्रश्न सं. 947 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार , भारतीय रेल पर 49,323 किलोमीटर कुल लंबाई वाली, जिनकी अनुमानित लागत 7.33 लाख करोड़ रुपये हैं, ऐसी 452 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (183 नई लाइन, 42 आमान परिवर्तन और 227 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 11,518 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च 2022 तक इन पर 2.35 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

ओडिशाः

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र सहित ओडिशा में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 55,759 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 4,609 किलोमीटर कुल लंबाई की 35 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (11 नई लाइनें, 1 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें 1039 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च 2022 तक 21,729 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

ओडिशा राज्य भारतीय रेल के पूर्व तट रेलवे , दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा कवर है। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board> About Indian Railways> Railway Board Directorates> Finance (Budget)> Rail Budget/ Pink Book (Year)> Railway wise works Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

s.k

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि का शीघ्र अधिग्रहण, वन विभाग द्वारा वानिकी स्वीकृति , लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का निक्षेपण, बाधक जनपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति , क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति , परियोजना स्थल की कानून एवं व्यवस्था स्थिति, परियोजना विशेष स्थल पर वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। इन सब बा ध्यताओं के बावजूद, रेल परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

सरकार द्वारा रेल परियोजनाओं के प्रभावी औ र शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें (i) गति शक्ति इकाई की स्थापना (ii) परियोजनाओं को वरीयता (iii) वरीयता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन का आबंटन (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की गहन निगरानी (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव स्वीकृति और परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुसरण करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 के बाद कमीशनिंग की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

2014 के बाद से, परियोजनाओं के लिए धन आवंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ओडिशा राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए 2014-19 के दौरान औसत वार्षिक बजट आबंटन को बढ़ाकर प्रति वर्ष 4,126 करोड़ रुपये कर दिया जो 2009-14 के दौरान 838 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था यह 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 392 % अधिक है। इन आबंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 4,568 करोड़ रुपये (2009-14 के वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 445% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 5,296 करोड़ रुपये (2009-14 की तुलना में औसत वार्षिक बजट आबंटन से 532% अधिक) और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6,471 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 672 % अधिक है) किया गया है । वित्त वर्ष 2022-23 में इन परियोजनाओं के लिए उच्चतम बजट परिव्य 9,734 करोड़ रुपये मुहैया कराया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय की तुलना में 1062% (838 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) अधिक है।

2014 -19 के दौरान, ओडिशा राज्य में पूर्ण तया/आंशिक रूप से पड़ने वाले 267 किलोमीटर (56 किलोमीटर नई लाइन, 83 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 128 किलोमीटर दोहरीकरण) लंबाई के खंड को 53.40 किलोमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से चालू किया गया है। यह कमीशनिंग वर्ष 2014-22 के दौरान 141.88 किलोमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़कर 1135 किलोमीटर (264 किलोमीटर नई लाइन और 871 किलोमीटर दोहरीकरण) हो गई जो वर्ष 2009-14 के दौरान प्राप्त वार्षिक कमीशनिंग दर (53.40 किलोमीटर/प्रतिवर्ष) की तुलना में 166% अधिक है।

*****

s.k